services in these areas. In respect of existing post offices also, some offices which were curtailed or closed in the Kashmir Valley due to unavoidable reasons are being reopened in a phased manner.

A target of 89 Panchayat Sanchar Sewa Kendras has also been allocated to Himachal Pradesh and Uttar Pradesh during the annual plan 1995-96. All the Panchayat Sanchar Sewa Kendras in Himachal Pradesh and some in Uttar Pradesh may be opened in the hilly areas. Further, the department's programme of modernisation, particularly through computer-based counter machines also cover selected post offices located in hilly and tribal areas where some of the office have been fully modernised by optimising the benefits of these counter machines. The department's programme for VSAT centres in selected hilly and tribal areas for expediting transfer of funds and providing other useful services. Efforts to provide basic infrastructure in respect of office buildings and staff quarters also extend to such areas.

(c) The regular measures for improvement of efficiency of service cover all offices and services in the country. In respect of new post offices to be opened, the department however, follows liberalised norms providing subsidy upto 85% of coast for hilly and tribal areas.

शिशुओं के लिये दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध पाउडर की मात्रा को सीमित करना

979. **श्री सोमपाल:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा शिशुओं के लिये दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध पाउडर की मात्रा को अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके विस्तृत कारण क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) सरकार का विचार निर्माताओं द्वारा शिशुओं के लिए तैयार किए जा रहे दूध उत्पादों और दूध पाउडर की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर और अन्य डाक सुविधाओं से विहीन गांव

980. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है जहां न तो डाकघर हैं और न ही लेटरबाक्स;

(ख) क्या दूरदराज के गांवों में डाक-टिकटों और अन्य डाक सामग्री की सदैव कमी रहती है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान ऐसे कितने गांवों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के सभी गांवों में कब तक डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के (श्री सुखराम): राज्य मंत्री (क) देश में बिना डाकघर और लैटर बाक्स वाले गांवों की संख्या, 31.03.1995 की स्थिति के अनुसार, क्रमशः विवरण। और 11 में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ख) जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि दूरदराज के इलाकों के डाकघरों में डाक-सामग्री की हमेशा कमी रहती है। कभी-कभी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ दूरदराज के इलाकों में थोड़े समय के लिए कतिपय मदों की कमी हुई थी।

(ग) देश के गांवों में, वर्ष 1995-96 के दौरान 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) देश के सभी गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना नहीं है। सरकार का लक्ष्य निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार गांवों में डाकघर खोलना है बशर्ते कि जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण-I

उन गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, जिनमें 31.3.95 की स्थिति के अनुसार डाकघर नहीं है।

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं है
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	12300
2.	असम	21117
3.	अरुणाचल प्रदेश	27
4.	बिहार	56524
5.	गोवा	182
6.	गुजरात	9949
7.	हरियाणा	4489
8.	हिमाचल प्रदेश	14385
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4995
10.	कर्नाटक	18828
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	61662
13.	महाराष्ट्र	29414
14.	मणिपुर	1364
15.	मेघालय	5044
16.	मिजोरम	348
17.	नागालैंड	936
18.	उड़ीसा	43486
19.	पंजाब	9072
20.	राजस्थान	28412
21.	सिक्किम	244
22.	तमिलनाडु	5484
23.	त्रिपुरा	4076
24.	उत्तर प्रदेश	94847
25.	पश्चिम बंगाल	30781
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार	113
2.	चण्डीगढ़	17
3.	दादर एवं नगर हवेली	38
4.	दमण एवं दीव	16
5.	दिल्ली	93
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडिचेरी	233
	अखिल भारतीय योग:	458476

विवरण-II

उन गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा जिनमें 31.3.95 की स्थिति के अनुसार लैटरबाक्स नहीं है।

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन गांवों की संख्या जिनमें लेटरबाक्स नहीं है
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	485
2.	असम	10388
3.	अरुणाचल प्रदेश	3074
4.	बिहार	41708
5.	गोवा	42
6.	गुजरात	352
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	11378
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2920
10.	कर्नाटक	9348
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	33290
13.	महाराष्ट्र	8976
14.	मणिपुर	931
15.	मेघालय	3968
16.	मिजोरम	264
17.	नागालैंड	598
18.	उड़ीसा	36205
19.	पंजाब	1676
20.	राजस्थान	17310
21.	सिक्किम	165
22.	तमिलनाडु	839
23.	त्रिपुरा	1773
24.	उत्तर प्रदेश	35571
25.	पश्चिम बंगाल	4720
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार	27
2.	चण्डीगढ़	—
3.	दादर एवं नगर हवेली	—
4.	दमण एवं दीव	—
5.	दिल्ली	—
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडिचेरी	62
	अखिल भारतीय योगः	226070